अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक में पारित वक्तव्य
2 नवंबर, 2010, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

1. श्रीमती सोनिया गांधी जी के चौथी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव–निर्वाचित सदस्य उन्हें बधाई देते हैं। उनके मार्गदर्शन में, केंद्र में दो बार कांग्रेसनीत यूपीए गठबंधन सरकार बनी है। अपने अथक प्रयासों और अपनी निःस्वार्थ सेवा से उन्होंने एक सौ पच्चीस वर्ष पुरानी पार्टी में नई जान फूंकी है और इससे पार्टी में नये रक्त का संचार हुआ है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को ग्रहण न करके बेमिसाल त्याग और बलिदान का उदाहरण पेश किया।

2. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव–निर्वाचित सदस्य डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में उनके बुद्धिमत्तापूर्ण और कुशल नेतृत्व की सराहना करते हैं। दुनियाभर में छाए आर्थिक संकट के दौरान उन्होंने भारत में आर्थिक विकास की उच्च दर बनाए रखकर देश की प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी की।

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा ही हर तरह की सांप्रदायिक सोच के खिलाफ वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष में सबसे आगे रही है। सदियों से हमारे देश की जो मिली–जुली तहजीब और संस्कृति रही है, उसे बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अपनी धर्म–निरपेक्ष प्रतिबद्धता को फिर दोहराती है। हाल ही की जांच–पड़ताल से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों की कलई खुल गई है। जांच से यह पता चलता है कि आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में इनके सदस्यों की संलिप्तता प्रतीत होती है। सांप्रदायिक और आतंकवादी तत्वों का स्रोत चाहे कुछ भी हो, उनका मकसद है हमारे राष्ट्रीय ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करना। हम पूरी ताकत से ऐसे तत्वों का मुकाबला करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन सभी ताकतों से लड़ेगी, जो सांप्रदायिक नफरत, कट्टरता और दुराग्रह फैलाकर लोगों को धर्म के आधार बांटते हैं।

4. मई, 2004 में, सत्ता में आने के बाद, कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यह बैठक उनकी सराहना करती है। सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उनकी सफलता का दारोमदार विभिन्न स्तरों पर हमारे कांग्रेस के पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर निर्भर है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि तमाम कल्याणकारी कार्यक्रमों का फायदा आम आदमी तक पहुंचे, खासकर समाज के कमज़ोर तबकों तक। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम उन्हीं के लिए ही बनाए गए हैं।

5. हाल ही के दिनों में जम्मू और कश्मीर में कानून–व्यवस्था की हालत बदतर हो गई थी। हालांकि, राज्य सरकार के सहयोग से वहां की स्थिति अब सामान्य हो रही है। संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति एक स्वागतयोग्य कदम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जिलों में जो माओवादी और नक्सली गतिविधियां चल रही हैं, उनसे कानून और व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इन कार्रवाइयों से तमाम मासूम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को जानें गई हैं और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति का नुक़सान पहुंचा है। देश के ख़िलाफ़ समाज के किसी भी तबके द्वारा सशस्त्र संघर्ष को बर्दाश्त नहीं क़िया जा सकता। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को हर ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। जन–जातीय और दूसरे वामपंथी